



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 368]	नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 3, 2018/आश्विन 11, 1940 (शक)
No. 368]	NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 3, 2018/ASVINA 11, 1940 (SAKA)

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 3 अक्टूबर, 2018

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[प्रशासक की नियुक्ति और निवेशकों को धन-वापसी (रिफंड) की प्रक्रिया] विनियम, 2018

सं. सेबी/ एल. ए. डी. - एन.आर. ओ/ जी. एन./ 2018/ 39.— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1) तथा धारा 28क के साथ पठित धारा 30, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 23अ और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19अ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

अध्याय-I

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रशासक की नियुक्ति और निवेशकों को धन-वापसी (रिफंड) की प्रक्रिया] विनियम, 2018 कहा जा सकेगा।

(2) वे राजपत्र में उनकी अधिसूचना की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएँ

2. (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

क) "अधिनियम" से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) [सेबी एक्ट, 1992] अभिप्रेत है;

- ख) **"प्रशासक"** से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के पास 'दिवाला का समाधान करने वाले पेशेवर व्यक्ति' (इन्सॉल्वेन्सी रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल) के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो और जिसे इन विनियमों के प्रयोजनार्थ वसूली अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया हो;
- ग) **"विज्ञापन"** में शामिल हैं -
- सूचनाएँ (नोटिस), विवरणिकाएँ (ब्रोशर), पुस्तिकाएँ (पैम्फलेट), परिपत्र (सर्कुलर), शो-कार्ड, प्रसूची (कैटेलॉग), विज्ञापन पट्ट (होर्डिंग), प्लेकार्ड, पोस्टर, समाचारपत्र में कुछ भी छपना, चित्र, फिल्मों और वृत्तचित्र (डॉक्यूमेंटरी); और
 - प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न कार्यक्रम या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कोई प्रचार;
- घ) **"लेखापरीक्षक"** (ऑडिटर) से कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनियों के लेखों (अकाउंट्स) की लेखापरीक्षा (का ऑडिट) करने के लिए योग्य (अर्हित) व्यक्ति अभिप्रेत है;
- ङ) **"बोर्ड"** से अधिनियम की धारा 3 के तहत स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अभिप्रेत है;
- च) **"प्रमाणपत्र"** से वसूली अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 28क या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्क्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956] की धारा 23अख या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (डिपॉज़िटरीज़ एक्ट, 1996) की धारा 19अख के तहत तैयार किया गया कथन अभिप्रेत है और जिसमें विक्रय प्रमाणपत्र (सेल सर्टिफिकेट) शामिल नहीं होगा;
- छ) **"चूककर्ता"** (डिफॉल्टर) से, इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो निर्धारित समयावधि के भीतर निवेशकों (विनिधानकर्ताओं) को धन-वापसी करने (पैसा लौटाने / रिफंड करने) के संबंध में बोर्ड के आदेश का पालन करने में या प्रत्यर्पण (डिस्गॉर्जमेंट) के संबंध में बोर्ड के आदेश का पालन करने में असफल रहा हो और जिसका उल्लेख प्रमाणपत्र में चूककर्ता के रूप में किया गया हो;
- ज) **"ई-नीलामी"** से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जाने वाली सार्वजनिक नीलामी (पब्लिक ऑक्शन) अभिप्रेत है;
- झ) **"ई-नीलामी एजेंसी"** से वह कंपनी अभिप्रेत है, जो ई-नीलामी का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती हो और जिसे वसूली अधिकारी द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों की नीलामी तथा बिक्री करने के प्रयोजनार्थ प्रशासक द्वारा नियुक्त किया गया हो;
- ञ) **"निवेशक"** से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका पता चल पाया हो या न चल पाया हो, जिसके पक्ष में धन-वापसी करने (पैसा लौटाने / रिफंड करने) का निदेश बोर्ड द्वारा दिया गया हो;
- ट) **"संपत्ति"** से अभिप्रेत है और जिसमें शामिल हैं - किसी भी प्रकार की आस्तियाँ (असेट्स), चाहे चल हों या अचल, मूर्त (टेंजिबल / कॉरपोरियल) हों या अमूर्त (इनटेंजिबल / इनकॉरपोरियल) और जिसमें शामिल हैं प्रतिभूतियाँ (सिक्क्यूरिटीज़), बैंक खाते, जमाएँ (डिपॉज़िट), कोई अधिकार या हित या कानूनी दस्तावेज या लिखत जो संपत्ति में हक या हित का सबूत हों तथा जहाँ संपत्ति किसी दूसरे रूप में बदली जा सकती हो वहाँ इस प्रकार बदले हुए रूप में संपत्ति और जिसमें संपत्ति से मिलने वाला पैसा (प्रोसीड्स / आगम) भी शामिल है;
- ठ) **"वसूली अधिकारी"** से बोर्ड का वह अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे लिखित रूप में साधारण या विशेष आदेश द्वारा, अधिनियम की धारा 28क या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 23अख या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19अख के तहत वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, प्राधिकृत किया गया हो;

- ड) **“धन-वापसी संबंधी आदेश”** (रिफंड ऑर्डर) से धन-वापसी करने के संबंध में निवेशकों को अधिनियम या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के तहत जारी किया गया बोर्ड का निदेश अभिप्रेत है;
- ढ) **“वसूली कार्यवाहियों”** से वसूली अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 28क या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 23अख या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19अख के तहत देय रकम की वसूली के लिए शुरू की गई कार्यवाहियाँ अभिप्रेत हैं;
- ण) **“रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक”** का वही अर्थ होगा जो कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 या उसके किसी अन्य कानूनी संशोधन के तहत इसके लिए नियत है।

(2) इन विनियमों में उपयोग किए गए तथा अपरिभाषित किंतु अधिनियम, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956, निक्षेपागार अधिनियम, 1996, आय-कर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची और आय-कर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम या उन नियमों में क्रमशः उनके लिए नियत हों।

लागू होना

3. (1) ये विनियम निम्नलिखित में से सभी के संबंध में या किसी एक के संबंध में लागू होंगे:

- क. बोर्ड द्वारा पारित किए गए प्रत्यर्पण (डिस्गॉर्जमेंट) या धन-वापसी संबंधी आदेशों का पालन करने में असफल रहने के अनुसरण में प्रशासक की नियुक्ति के संबंध में;
- ख. अधिनियम के तहत बोर्ड के वसूली अधिकारी द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों की बिक्री के संबंध में;
- ग. धन-वापसी (रिफंड) करने के प्रयोजनार्थ, दावे संबंधी दस्तावेज लेने और निवेशकों के दावों का सत्यापन करने के संबंध में;
- घ. बोर्ड द्वारा पारित किए गए प्रत्यर्पण (डिस्गॉर्जमेंट) या धन-वापसी संबंधी आदेशों के अनुसरण में निवेशकों को धन-वापसी करने के संबंध में;
- ड. बोर्ड के निदेशानुसार प्रत्यर्पण की रकमों की वसूली करने के संबंध में;
- च. उससे आनुषंगिक या संबंधित किसी कार्य के संबंध में।

(2) जब तक कि विशिष्ट रूप से अन्यथा आदेश न दिया गया हो, ये विनियम उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहाँ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) या न्यायालय ने वसूली और/या निवेशकों को पैसा लौटाने के प्रयोजनार्थ प्रशासक या किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर लिया हो।

(3) इन विनियमों के प्रावधान प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के तहत कार्यवाहियों के संबंध में, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।

अध्याय-II

भाग-I - प्रशासक

प्रशासक की नियुक्ति

4. इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, बोर्ड, वसूली अधिकारी द्वारा चूककर्ता (डिफॉल्टर) की संपत्तियों की कुर्की किए जाने के बाद, उसी प्रकार प्रशासक को नियुक्त करेगा जैसा निर्धारित किया गया हो।

प्रशासक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड

5. (1) प्रशासक वह व्यक्ति होगा जो भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के पास 'दिवाला का समाधान करने वाले पेशेवर व्यक्ति' (इन्सॉल्वेन्सी रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल) के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो और जिसे बोर्ड द्वारा समय-समय पर सूची में शामिल किया जाए।

(2) किसी भी व्यक्ति को प्रशासक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, जहाँ ऐसी नियुक्ति के प्रति उन आधारों पर आपत्ति जताई जा सकती हो जिनसे ऐसे व्यक्ति की स्वतंत्रता या निष्पक्षता को लेकर शंकाएं उत्पन्न हो जाएं और जो उचित भी लगती हों:

परंतु यह कि प्रशासक की नियुक्ति को लेकर यदि ऐसा कोई प्रश्न उठे जो हित-विरोध के मुद्दे से जुड़ा हो, तो उसका निर्णय वसूली अधिकारी द्वारा लिया जाएगा।

(3) प्रशासक बोर्ड के पास यह वचन प्रस्तुत करेगा कि चूककर्ता, उसके निदेशकों, संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स), प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों (की मैनेजिरियल पर्सोनल) और उसकी समूह (ग्रुप) एंटिटियों के साथ उसका कोई हित-विरोध नहीं है।

(4) प्रशासक बोर्ड को ऐसे किसी हित-विरोध की जानकारी भी तुरंत प्रकट करेगा, जो उसके कार्यकाल के दौरान उसकी जानकारी में आए।

(5) इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, प्रशासक को भारतीय दंड संहिता (1860 की 45) की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक (पब्लिक सर्वेंट) माना जाएगा, और तदनुसार अधिनियम की धारा 22 तथा 23 उस पर लागू होगी।

नियुक्ति की शर्तें आदि

6. नियुक्ति की शर्तें आदि (जिनमें पारिश्रमिक शामिल है) प्रत्येक मामले में, बोर्ड द्वारा इस आधार पर निर्धारित की जाएंगी कि कार्य कितना है, निवेशक कितने हैं और कितना पैसा लगा हुआ है।

भाग-II - प्रशासक के कार्य

7. (1) प्रशासक निम्नलिखित कार्य करेगा -

- (क) चूककर्ता या किसी अन्य व्यक्ति से, कोई जानकारी या दस्तावेज प्राप्त करना [जिसमें संपत्तियों के स्वामित्व और कब्जे से संबंधित दस्तावेज, निवेशकों से जुटाई गई रकम, निवेशकों के दावों, निवेशकों को की गई धन-वापसी (रिफंड) से संबंधित ब्यौरे शामिल हैं], जैसा वसूली अधिकारी द्वारा निदेश दिया जाए;
- (ख) उन संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार करना जिनकी कुर्की वसूली अधिकारी द्वारा की गई हो, जिनमें वे अतिरिक्त संपत्तियाँ भी शामिल हैं जो वसूली अधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपी गई हों और वे संपत्तियाँ जिनका उल्लेख कुर्की आदेश में न हो;
- (ग) चूककर्ता के बैंक खातों तथा डीमैट खातों और उनमें पड़े पैसों तथा पड़ी प्रतिभूतियों का रिकॉर्ड तैयार करना;
- (घ) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संपत्ति की बिक्री की घोषणा करवाना और ऐसी घोषणा की प्रति लगवाना (चिपकाना);
- (ङ) आस्तियों (असेट्स) की बिक्री से वसूल किया गया पैसा जमा करने और निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित बैंक में बैंक खाता (जिस पर व्याज मिलता हो) खोलना, जो वसूली अधिकारी के नियंत्रण में हो;
- (च) इन विनियमों के अनुसार या वसूली अधिकारी के निदेशानुसार कुर्की की गई संपत्तियों की बिक्री करना;
- (छ) धन-वापसी (रिफंड) के लिए बोर्ड के आदेश के अनुसरण में, निवेशकों को पैसा लौटाने के प्रयोजनार्थ, उसी

प्रकार दावे मंगवाना, जैसा इन विनियमों में निर्धारित किया गया है या जैसा वसूली अधिकारी द्वारा निदेश दिया जाए;

- (ज) निवेशकों के दावों का सत्यापन करना और निवेशकों को पैसा लौटाने के संबंध में चूककर्ता के उन दावों का भी सत्यापन करना, जिनके संबंध में उसने दस्तावेजी सबूत के आधार पर यह दावा किया हो कि पैसा या तो आंशिक रूप से या पूरी तरह से अदा कर दिया गया है;

स्पष्टीकरण - सत्यापन में न्यायालयिक लेखापरीक्षा (फॉरेंसिक ऑडिटिंग) शामिल हो सकती है।

- (झ) वसूली अधिकारी की पूर्व-मंजूरी से ऐसा कोई अन्य जरूरी आनुषंगिक एवं अनुपूरक कार्य करना, जो इन विनियमों के तहत उसकी बाध्यताओं को पूरा करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षित हो।

- (2) इन विनियमों के तहत कार्यों का निर्वहन करते समय, प्रशासक -

- (क) दस्तावेजी सबूत के आधार पर निवेशकों के दावों का सत्यापन करने के लिए और प्रशासक को प्रमाणित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पीयर रिव्यूड चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवाएँ ले सकेगा;
- (ख) वसूली अधिकारी द्वारा कुर्क की गई चूककर्ता की संपत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए और बोर्ड द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों (गाइडलाइन्स) के अनुसार प्रमाणित मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक की सेवाएँ लेगा;
- (ग) पैसा लौटाने की पूरी प्रक्रिया का प्रबंधन करने के लिए, बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता (रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट) या ऐसी एजेंसी, जो वसूली अधिकारी द्वारा मंजूर की जाए, की सेवाएँ ले सकेगा;

परंतु यह कि ऐसी सेवाओं के लिए अदा की जाने वाली फीस प्रशासक द्वारा संबंधित कारकों को ध्यान में रखकर तय की जाएगी, जिनमें शामिल हैं -

- (क) निवेशक कितने हैं और कितने दावे किए गए हैं;
- (ख) कार्य कितना है;
- (ग) कितनी आस्तियों (असेट्स) का मूल्यांकन किया जाना है;
- (घ) संपत्ति कहाँ स्थित है और वह मूल्यांकक के कारबार के स्थान से कितनी नज़दीक है;

और ऐसी फीस बोर्ड द्वारा प्रशासक के लिए तय किए गए कुल पारिश्रमिक के दायरे में ही आएगी;

परंतु यह और कि प्रशासक द्वारा नियुक्त मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) या ऐसे अन्य व्यक्ति का ऐसा कोई हित-विरोध न हो, जिससे कि उनकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता पर आंच आए।

- (3) प्रशासक सौंपे गए कार्य (जिसमें संपत्तियों की बिक्री के अनुसरण में रकम वसूल करना और निवेशकों को पैसा लौटाना शामिल है) की प्रगति के संबंध में मासिक रिपोर्ट या रिपोर्ट (जब भी वसूली अधिकारी द्वारा मांगी जाए) प्रस्तुत करेगा।

भाग-III - संपत्तियों की बिक्री

8. (1) प्रशासक संपत्तियों की बिक्री की प्रक्रिया, ऐसी संपत्तियों का रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक से स्वतंत्र मूल्यांकन करवाने के बाद ही, शुरू करेगा।

(2) मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, वसूली अधिकारी वह आरक्षित कीमत (रिज़र्व प्राइस) तय कर सकेगा जिससे कम कीमत पर संपत्ति की बिक्री नहीं की जा सकेगी।

(3) प्रशासक ई-नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से संपत्तियों की बिक्री शुरू कर सकेगा तथा इस प्रयोजनार्थ ई-नीलामी एजेंसी की सेवाएँ ले सकेगा और वसूली अधिकारी के परामर्श से तब तक नीलामी की प्रक्रिया दोहराएगा, जब तक ऐसी संपत्तियों की बिक्री आदि न हो जाए।

(4) संपत्तियों की बिक्री आदि की प्रक्रिया वसूली अधिकारी की देखरेख में चलेगी।

(5) बिक्री पूरी होने पर और बिक्री के बाद पैसा मिल जाने पर, वसूली अधिकारी अधिनियम के अनुसार ऐसी बिक्री की पुष्टि करते हुए एक आदेश जारी करेगा।

(6) चूककर्ता की संपत्तियों की बिक्री के संबंध में वसूल की गई रकम विनियम 7 के खंड (ड) के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एक अलग बैंक खाते में जमा की जाएगी, और ऐसा खाता वसूली अधिकारी के नियंत्रण में होगा।

भाग-IV - धन-वापसी (रिफंड)

निवेशकों को धन-वापसी (रिफंड)

9. (1) निवेशकों से दावे आमंत्रित करने के प्रयोजनार्थ, प्रशासक –

(क) पूरे देश में परिचालन वाले एक अंग्रेजी तथा एक हिन्दी समाचारपत्र में विज्ञापन जारी करेगा और यदि वसूली अधिकारी (रिकवरी ऑफिसर) द्वारा निदेश दिया जाए, तो उस क्षेत्र (उन क्षेत्रों) में परिचालित होने वाले स्थानीय भाषा के समाचारपत्र (समाचारपत्रों) में ऐसा विज्ञापन जारी करेगा जहाँ निवेशक ज्यादा हों;

(ख) चूककर्ता (डिफॉल्टर) को उसके वेबसाइट (यदि उपलब्ध हो) पर विज्ञापन जारी करने का निदेश देगा।

(2) उप-विनियम (1) में उल्लिखित विज्ञापन को बोर्ड के वेबसाइट पर भी डाला जा सकेगा।

(3) उप-विनियम (1) में उल्लिखित विज्ञापनों में वे निदेश शामिल होंगे कि निवेशकों द्वारा दावे किस प्रकार किए जाएँ और दावे से संबंधित उनके आवेदनों को सत्यापित करने तथा उनके संबंध में कार्यवाही करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएँ एवं क्या-क्या जानकारी प्रस्तुत की जाए।

(4) निवेशकों से दावे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आमंत्रित किए जाएंगे या प्रशासक के कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे:

परंतु यह कि निवेशकों की ओर से जो दावे बोर्ड को प्राप्त हों (यदि कोई हों) और जो प्रशासक को भिजवाए जाएँ, उन्हें भी प्रशासक द्वारा रखे जा रहे संबंधित रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा।

(5) प्रशासक या प्रशासक द्वारा नियुक्त किया गया चार्टर्ड अकाउंटेंट निवेशकों को वितरित किए जाने हेतु उपलब्ध धनराशि की तुलना में कुल पात्र दावों पर विचार करेगा, ताकि यह तय किया जा सके कि वसूली अधिकारी द्वारा जारी किए गए निदेश के अनुसार निवेशकों को पूरा पैसा लौटाया जा सकेगा या पैसा समानुपातिक आधार पर ही लौटाया जा सकेगा।

(6) पात्रता सुनिश्चित हो जाने पर, प्रशासक, वसूली अधिकारी के परामर्श से, पात्र निवेशकों को पैसा केवल, भुगतान आदेशों (पे ऑर्डर्स), मांग ड्राफ्टों (डिमांड ड्राफ्ट्स) के माध्यम से ही लौटाएगा और एनईएफटी या आरटीजीएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतरित करके ही लौटाएगा।

(7) धन-वापसी (रिफंड) की प्रक्रिया एक उपयुक्त अवधि तक खुली रखी जाएगी, जैसा वसूली अधिकारी के परामर्श से तय किया जाए।

(8) निवेशकों के सभी स्वीकार्य दावों और अन्य खर्चे आदि पूरे करने के पश्चात्, एस्क्रो (निलंब) बैंक खाते (जिस पर ब्याज मिलता हो) में पड़ी शेष धनराशि तीन वर्षों की अवधि तक उसी खाते में रखी जाएगी, ताकि किसी निवेशक (जिसे भुगतान न किया गया हो) से प्राप्त होने वाले दावों के संबंध में धन-वापसी की जा सके।

(9) उप-विनियम (8) के तहत निर्धारित की गई अवधि पूरी होने के पश्चात्, निवेशकों को न लौटाया गया पैसा (यदि कोई हो) बोर्ड की निवेशक संरक्षण और शिक्षण निधि में अंतरित (ट्रांसफर) कर दिया जाएगा।

(10) यदि किसी निवेशक (जिसे भुगतान न किया गया हो) की ओर से कोई दावा धन-वापसी (रिफंड) की प्रक्रिया के बंद होने के बाद प्राप्त होता है, तो ऐसे में वसूली अधिकारी के परामर्श से प्रशासक द्वारा आवश्यक सत्यापन करने के पश्चात्, धन-वापसी निवेशक संरक्षण और शिक्षण निधि में से की जा सकेगी:

परंतु यह कि दावा, उप-विनियम (9) के अनुसार निवेशक संरक्षण और शिक्षण निधि में पैसा अंतरित (ट्रांसफर) किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के भीतर, किया जाएगा।

(11) चूककर्ता और कंपनी अधिनियम, 2013 (कंपनीज़ एक्ट, 2013) की धारा 2 के तहत यथा परिभाषित चूककर्ता अधिकारी, जो भी लागू हो, यह वचन प्रस्तुत करेंगे कि यदि किसी निवेशक की ओर से बोर्ड को भविष्य में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो वे भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

प्रशासन और पैसा लौटाने की प्रक्रिया में होने वाले खर्चे

10. (1) संपत्तियों की बिक्री, निवेशकों के दावों के सत्यापन, प्रशासक के पारिश्रमिक [जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट या मूल्यांकक या प्रशासक द्वारा नियुक्त किए गए अन्य व्यक्ति तथा रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता (रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट) को अदा की जाने वाली फीस, यदि कोई हो, शामिल हैं] के संबंध में होने वाले पूरे खर्चे तथा वसूली और/या पैसा लौटाने की प्रक्रिया के संबंध में होने वाले दूसरे पूरे खर्चे चूककर्ता (चूककर्ताओं) द्वारा उठाए जाएंगे, ऐसा न किए जाने पर, बोर्ड द्वारा वसूल किए गए पैसों में से दूसरी देनदारियों की तुलना में उपरोक्त को वरीयता दी जाएगी।

(2) उप-विनियम (1) में उल्लिखित खर्चे आदि वाजिव हों और जो इन विनियमों में उल्लिखित कार्य और प्रयोजनों से सीधे तौर पर जुड़े हुए हों और उनके लिए आवश्यक हों।

(3) जहाँ प्रशासक को ऐसे व्यक्ति के अनुरोध पर नियुक्त किया जाता हो जिसके खिलाफ बोर्ड द्वारा प्रत्यर्पण (डिस्मॉर्जमेंट) या धन-वापसी (रिफंड) संबंधी आदेश जारी किया गया था, वहाँ प्रशासक का पारिश्रमिक तथा वसूली और/या निवेशकों को की जाने वाली धन-वापसी से संबंधित दूसरे खर्चे ऐसे व्यक्ति द्वारा उठाए जाएंगे।

बिक्री से आए पैसों (सेल प्रोसीड्स) के वितरण में वरीयता

11. चूककर्ता की संपत्तियों की बिक्री से आए पैसों को नीचे दिए हुए वरीयता क्रम के अनुसार वितरित किया जाएगा, अर्थात्, -

- i. बोर्ड द्वारा किए गए प्रशासनिक खर्चे, यदि कोई हों, और इन विनियमों के तहत अपने कार्यों के निर्वहन हेतु प्रशासक को तथा प्रशासक द्वारा नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियों को देय फीस एवं प्रभार आदि;
- ii. प्रत्यर्पण और/या निवेशकों को देय रकम:
परंतु यह कि बोर्ड प्रशासक को उपयुक्त समय पर वसूल किए गए पैसों से निवेशकों को धन-वापसी करने की प्रक्रिया शुरू करने का निदेश दे सकेगा। इस प्रयोजनार्थ, प्रशासक हिस्सों में दावे मंगवा सकेगा
- iii. अधिनियम, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956] या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (डिपॉजिटरीज़ एक्ट, 1996) के प्रावधानों के तहत बोर्ड को चूककर्ता की ओर से देय कोई अन्य शास्ति (पेनल्टी) या फीस।

वह पैसा वापस लौटाना जो देनदारी (दायित्व) से अधिक हो

12. यदि चूककर्ता की संपत्तियों की बिक्री से वसूल किया गया पैसा प्रमाणपत्र के तहत उसकी ओर से देय रकम और लागू ब्याज तथा अन्य शुल्क की रकम से अधिक होता है, तो वह पैसा चूककर्ता को धन-वापसी (रिफंड) की प्रक्रिया पूरी होने

की तारीख से तीन वर्ष पूरे होने के पश्चात् अदा कर दिया जाएगा।

पैसा लौटाने (रीपेमेंट) के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करना

13. सभी निवेशकों को पैसा लौटाने की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् या चूककर्ता से प्रत्यर्पण (डिस्गॉर्जमेंट) की रकम वसूल किए जाने के पश्चात्, प्रशासक, यथास्थिति, वसूली अधिकारी या बोर्ड के पास, यथा निर्धारित अवधि के भीतर, पैसा लौटाने (रीपेमेंट) / वसूली (रिकवरी) के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करेगा।

भाग-V – रकम का प्रत्यर्पण (डिस्गॉर्जमेंट)

14. बोर्ड के आदेशानुसार प्रत्यर्पण की रकम की वसूली से संबंधित इन विनियमों के प्रावधान लागू होंगे (जहाँ तक वे लागू हों), और इस प्रकार वसूल की गई प्रत्यर्पण की रकम बोर्ड की निवेशक संरक्षण और शिक्षण निधि में जमा करा दी जाएगी:

परंतु यह कि प्रत्यर्पण की रकम निवेशकों को तभी अदा की जाएगी, जब बोर्ड द्वारा पारित किए गए आदेश में यह उल्लेख हो कि पात्र निवेशक कौन हैं, और ऐसे भुगतान के बाद शेष रकम (यदि कोई हो) बोर्ड की निवेशक संरक्षण और शिक्षण निधि में जमा करा दी जाएगी।

भाग-VI - सामान्य बाध्यताएँ और जिम्मेदारियाँ

बाध्यताएँ और जिम्मेदारियाँ

15. प्रशासक –

- क) अपने समस्त कारबार संचालन में सत्यनिष्ठा, शीघ्रता और निष्पक्षता के उच्च स्तर बनाए रखेगा।
 - ख) अपने समस्त कारबार संचालन में पूरा कौशल, पूरी सावधानी और पूरी तत्परता बरतेगा।
 - ग) किन्हीं तथ्यों या परिस्थितियों को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं करेगा और ऐसे किसी कार्य में लिप्त होने से बचेगा जिससे कि उस पेशे की बदनामी हो।
 - घ) पेशेवर व्यक्ति के नाते व्यवहार करते समय पूरी निष्पक्षता के साथ कार्य करेगा और साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि संपत्तियों की बिक्री, दावों के सत्यापन और धन-वापसी (रिफंड) के संबंध में लिए जाने वाले सभी निर्णय बिना किसी पक्षपात के लिए जाएं, उनमें कोई हित-विरोध न हो, वे बिना किसी दबाव के लिए जाएं, या उनके संबंध में कोई पक्ष अनुचित तरीके से प्रभाव न डाले, फिर चाहे ऐसा प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से।
 - ङ) चूककर्ता की किन्हीं आस्तियों (असेट्स) को, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, अर्जित नहीं करेगा।
 - च) पेशेवर व्यक्ति के नाते सभी संबंधों में पूरी स्वतंत्रता बनाए रखेगा और यथास्थिति, सत्यापन तथा धन-वापसी (रिफंड) की प्रक्रिया का संचालन इस प्रकार करेगा कि उस पर कोई बाहरी प्रभाव न पड़े।
 - छ) कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं छिपाएगा अथवा वसूली अधिकारी या बोर्ड के समक्ष जानबूझकर कोई भ्रामक कथन नहीं करेगा।
 - ज) असद्व्यवहारपूर्वक कार्य नहीं करेगा या विनियमों के तहत कार्यों तथा कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लापरवाही नहीं बरतेगा।
 - झ) वसूली अधिकारी द्वारा निर्धारित की गई समय-सीमा के भीतर, ऐसी समस्त जानकारी और रिकॉर्ड प्रस्तुत करेगा, जैसी वसूली अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाए।
 - ञ) यह सुनिश्चित करेगा कि संपत्तियों की बिक्री, सत्यापन और धन-वापसी की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी की गोपनीयता सदैव बनी रहे:
- परंतु यह कि प्रशासक वसूली अधिकारी या बोर्ड द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किए जाने के पश्चात् कोई

जानकारी प्रकट कर सकेगा।

- ट) सत्यापन और धन-वापसी की प्रक्रिया में आने वाला समस्त खर्चा प्रकट करेगा और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि ऐसे खर्चे वाजिब हों।
- ठ) अपनी नियुक्ति से संबंधित शर्तों आदि का पालन करेगा।

अध्याय-III

चूक के मामले में कार्रवाई

प्रशासक द्वारा की गई चूक के मामले में

16. (1) वसूली अधिकारी, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, प्रशासक को बदलने की सिफारिश कर सकेगा, यदि प्रशासक –

- क) नियुक्ति की शर्तों आदि का पालन करने में असफल रहा हो;
- ख) ने ऐसे मूल्यांककों या चार्टर्ड अकाउंटेंटों या ऐसे अन्य व्यक्तियों की सेवाएँ ली हों, जो ऐसा कार्य करने के लिए पात्र न हों;
- ग) इन विनियमों के तहत निर्धारित की गई किन्हीं बाध्यताओं और जिम्मेदारियों का पालन करने में असफल रहा हो;
- घ) ने वसूली अधिकारी या बोर्ड के अनुदेशों के विपरीत कार्य किया हो; या
- ङ) इस तरह से कार्य किया हो, जिससे निवेशकों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

(2) उप-विनियम (1) के तहत उल्लिखित कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वसूली अधिकारी अधिनियम के तहत उपयुक्त कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश कर सकेगा।

(3) ऐसी सिफारिश प्राप्त होने पर या स्वप्रेरणा से, बोर्ड अधिनियम के तहत प्रशासक या ऐसे मध्यवर्ती या प्रशासक द्वारा नियुक्त किए गए ऐसे अन्य व्यक्ति के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई कर सकेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- (क) पैनल से ऐसे प्रशासक को हटाना;
- (ख) प्रशासक [जो 'दिवाला का समाधान करने वाला पेशेवर व्यक्ति' (इन्सॉल्वेन्सी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल) हो] के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई के लिए मामले को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के पास भिजवाना; और
- (ग) ऐसे व्यक्ति को प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में पेशेवर व्यक्ति की हैसियत से क्रियाकलाप करने से रोकते हुए उपयुक्त निदेश जारी करना।

(4) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड से प्रशासक का रजिस्ट्रीकरण रद्द या निलंबित होने की दशा में, बोर्ड प्रशासक को बदल देगा।

अध्याय-IV

विविध

स्पष्टीकरण जारी करने की बोर्ड की शक्ति

17. इन विनियमों के लागू होने या इनकी व्याख्या के संबंध में किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए, बोर्ड स्पष्टीकरण और दिशानिर्देश (गाइडलाइन्स) जारी कर सकेगा, जो भी जरूरी समझे जाएं।

फॉर्म

18. बोर्ड या वसूली अधिकारी इन विनियमों के तहत जारी किए जाने वाले ओदश, सूचना (नोटिस), वारंट, या

प्रमाणपत्र के संबंध में फॉर्म निर्धारित कर सकेगा।

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./245/18]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd of October, 2018

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(APPOINTMENT OF ADMINISTRATOR AND PROCEDURE FOR REFUNDING TO THE INVESTORS) REGULATIONS, 2018

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/39.—In exercise of the powers conferred by section 30 read with sub-section (1) of section 11 and section 28A of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), section 23JB of the Securities Contracts (Regulations) Act, 1956 and section 19-IB of the Depositories Act, 1996, the Board hereby makes the following regulations, namely,-

CHAPTER I

Preliminary

Short title and commencement

1. (1) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Appointment of Administrator and Procedure for Refunding to the Investors) Regulations, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their notification in the Official Gazette.

Definitions

2. (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

- a) “**Act**” means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 [15 of 1992];
- b) “**Administrator**” means a person registered with the Insolvency and Bankruptcy Board of India as an Insolvency Resolution Professional and who has been engaged by the Recovery Officer for the purposes of these regulations.
- c) “**advertisement**” includes -
 - (i) notices, brochures, pamphlets, circulars, show-cards, catalogues, hoardings, placards, posters, insertions in newspapers, pictures, films and documentaries; and
 - (ii) any publicity through print medium, radio, television programmes or electronic media;
- d) “**auditor**” means a person qualified to audit the accounts of companies under the Companies Act, 2013;
- e) “**Board**” means the Securities and Exchange Board of India established under section 3 of the Act;
- f) “**certificate**” means the statement drawn up by the Recovery Officer under section 28A of the Act or section 23JB of the Securities Contracts (Regulations) Act, 1956 or section 19-IB of the Depositories Act, 1996 and shall not include a sale certificate;
- g) “**defaulter**” for the purposes of these regulations, means a person who has failed to comply with an order of the Board to refund monies to the investors or an order of the Board for disgorgement within the specified time period and who is mentioned as a defaulter in the certificate;
- h) “**e-auction**” means the public auction conducted through electronic mode;
- i) “**e-auction agency**” means a company providing an e-auction platform which is engaged by the Administrator for the purposes of auctioning and selling properties attached by the Recovery Officer;
- j) “**investor**” means the person, whether identified or not, in whose favour the refund of monies had been directed by the Board;
- k) “**property**” means and includes assets of any kind, whether movable or immovable, tangible or intangible, corporeal or incorporeal and includes securities, bank accounts, deposits, any right or interest or legal documents or instruments evidencing title to or interest in the property and where the property is capable of

conversion into some other form, then the property in the converted form and also includes the proceeds from the property.

- l) **“Recovery Officer”** means an officer of the Board, who is authorised by a general or special order in writing, to exercise the powers of a recovery officer under section 28A of the Act or section 23JB of the Securities Contracts (Regulations) Act, 1956 or section 19-IB of the Depositories Act, 1996;
- m) **“refund order”** means a direction of the Board, issued under the Act or the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 or the Depositories Act, 1996, to refund monies to the investors;
- n) **“recovery proceedings”** means the proceedings for recovery of dues initiated by a recovery officer under section 28A of the Act or section 23JB of the Securities Contracts (Regulations) Act, 1956 or section 19-IB of the Depositories Act, 1996;
- o) **“registered valuer”** shall have the meaning assigned to it under the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017 or any other statutory modification thereof;

(2) Words and expressions used and not defined in this regulations but defined in the Act, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, the Depositories Act, 1996, the Second Schedule to the Income-tax Act, 1961 and the Income-tax (Certificate Proceeding), Rules, 1962, shall have the meanings respectively assigned to them in that Act and Rules respectively.

Applicability

3. (1) These regulations shall be applicable for all or any of the following:

- a. appointment of Administrator pursuant to failure to comply with disgorgement or refund orders passed by the Board;
- b. sale of properties attached by the Recovery Officer of the Board under the Act;
- c. collection of claim documents and verification of claims of investors for the purpose of effecting refunds;
- d. refund of monies to the investors pursuant to disgorgement or refund orders passed by the Board;
- e. recovery of disgorgement amounts directed by the Board;
- f. any act incidental or connected thereto.

(2) Unless otherwise specifically ordered, these regulations shall not be applicable to cases where the Securities Appellate Tribunal or a Court has appointed an administrator or any other person for the purposes of recovery and/or repayment to investors.

(3) The provisions of these regulations shall apply mutatis mutandis in respect of the proceedings under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 or the Depositories Act, 1996.

CHAPTER II

Part I - Administrator

Appointment of an Administrator

4. For the purposes of these regulations, the Board shall, after attachment of the properties of the defaulter by the Recovery Officer, appoint an Administrator in the manner specified.

Eligibility norms for appointment as an Administrator

5. (1) The Administrator shall be a person registered with the Insolvency and Bankruptcy Board of India as an Insolvency Resolution Professional and empanelled by the Board from time to time.

(2) No person shall be appointed as an Administrator where such an appointment may be objected to on the grounds that give rise to justifiable doubts as to the independence or impartiality of such a person:

Provided that any question involving issues of conflict of interest in the appointment of an Administrator shall be decided by the Recovery Officer.

(3) The Administrator shall provide an undertaking to the Board of absence of any conflict of interest with the defaulter, its directors, promoters, key managerial personnel and its group entities.

(4) The Administrator shall also forthwith disclose to the Board any conflict of interest which may come to his knowledge during his tenure:

(5) For the purposes of these regulations, the Administrator shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860) and sections 22 and 23 of the Act shall accordingly apply to him.

Terms of appointment

6. The terms and conditions of appointment including remuneration shall be specified by the Board, on a case to case basis, after taking into consideration the quantum of work, the number of investors and the quantum of money involved.

Part II - Functions of the Administrator

7. (1) An Administrator shall perform the following functions –

- (a) As may be directed by the Recovery Officer, obtain from the defaulter or any other person, any information or document including documents relating to ownership and possession of properties, details of amount raised from investors, claims of investors, amount claimed to have been refunded to investors;
- (b) Make a record of the properties that have been attached by the Recovery Officer including the additional properties that have been entrusted by the Recovery Officer from time to time and those properties which are not part of the attachment order;
- (c) Make a record of the bank accounts and dematerialised accounts of the defaulter and value of the monies and securities held thereunder;
- (d) Arrange for a proclamation for the sale of the property and arrange affixation of the copy of such proclamation in accordance with the provisions of the Act;
- (e) Open an interest bearing bank account, under the control of the Recovery Officer, with a scheduled public sector bank for depositing the proceeds of the money recovered from the sale of the assets and for making repayment to the investors;
- (f) Sell the attached properties in accordance with these regulations or as may be directed by the Recovery Officer;
- (g) Call for claims, in the manner specified in these regulations or as may be directed by the Recovery Officer, for the purposes of repayment to investors, pursuant to an order of the Board for refunds;
- (h) Verify the claims of investors and also that of the defaulter in respect of repayment of monies, either partly paid or wholly paid, claimed to have been made to investors on the basis of documentary evidence:

Explanation – Verification may involve forensic auditing.

- (i) Carry out any other necessary incidental and supplementary act, with the prior approval of the Recovery Officer that may be required for the purpose of carrying out its obligations under these regulations.

(2) While discharging the functions under these regulations, the Administrator -

- (a) may engage the services of a peer reviewed chartered accountant for verifying the claims of investors on the basis of documentary evidence and for submission of a certified report to the Administrator;
- (b) shall engage the services of a registered valuer to evaluate the properties of defaulter that are attached by the Recovery Officer and for submission of a certified valuation report in accordance with the guidelines issued by the Board;
- (c) may engage the services of a registrar and share transfer agent registered with the Board or such other agency as may be approved by the Recovery Officer, for managing the entire repayment process :

Provided that the fees paid for such services shall be fixed by the Administrator taking into account the relevant factors including –

- (a) the number of investors and the claims that are made;
- (b) quantum of work involved;
- (c) the number of assets to be evaluated;
- (d) the geographical location of the property and its proximity with the valuer's place of business;

and such fees shall be within the overall remuneration fixed by the Board for the Administrator:

Provided further that the intermediary or such other person engaged by the Administrator, shall not have any conflict of interest which would impede their independence or impartiality.

(3) The Administrator shall submit a monthly report or a report as and when called for by the Recovery Officer on the progress of work entrusted including the monies realised pursuant to the sale of the properties and the repayments made to the investors.

Part III – Sale of properties

8. (1) The Administrator shall undertake the process of sale of properties after conducting an independent valuation of such properties by a registered valuer.
- (2) After considering the valuation report, the Recovery Officer may decide on the reserve price below which the property may not be sold.
- (3) The Administrator may undertake the sale of properties through e-auction process and for this purpose engage an e-auction agency and shall in consultation with the Recovery Officer repeat the auction process till the time such properties are disposed off.
- (4) The process of disposing off the properties shall be under the supervision of the Recovery Officer.
- (5) On completion of the sale and receipt of the sale consideration, the Recovery Officer shall issue an order confirming such sale in accordance with the Act.
- (6) The amount realized in respect of sale of properties of the defaulter shall be deposited in a separate bank account with a scheduled public sector bank in terms of clause (e) of regulation 7 and such account shall be under the control of the Recovery Officer.

Part IV - Refund of monies

Refund to investors

9. (1) For the purposes of inviting claims from the investors, the Administrator shall -
- (a) issue advertisements in an English and a Hindi newspaper having nationwide circulation and if so directed by the Recovery Officer, issue such advertisement in vernacular newspaper(s) having circulation in the area(s) where the investors are concentrated;
- (b) direct the defaulter to issue advertisement in its website, if available.
- (2) The advertisement referred to sub-regulation (1) may also be hosted on the website of the Board.
- (3) The advertisements referred to in sub-regulation (1) shall contain instructions on the manner of making claims by investors and the documents and information that are to be submitted for verifying and processing their claim applications.
- (4) The invitation of claims from the investors shall be through electronic mode or be received in the office of the Administrator:
- Provided that the investors' claims received, if any, by the Board and forwarded to the Administrator shall also be included in the relevant records maintained by the Administrator.
- (5) The Administrator or the chartered accountant engaged by the Administrator, shall consider the total eligible claims as against the monies available for distribution to investors in order to determine whether the whole amount or a proportionate amount may be repaid to the investors as may be directed by the Recovery Officer.
- (6) Upon ascertaining the eligibility, the Administrator in consultation with the Recovery Officer, shall repay the money to the eligible investors only through pay orders, demand drafts and electronic transfer through NEFT or RTGS.
- (7) The refund process shall be kept open for an appropriate period as may be decided in consultation with the Recovery Officer.
- (8) The monies remaining in the interest bearing escrow bank account after satisfying all the permissible claims of investors and other charges, shall be retained therein for a period of three years in order to meet the claims that may be received from any unpaid investor.
- (9) Upon completion of the period specified under sub-regulation (8), the unpaid monies due to investors, if any, shall be transferred to the Investor Protection and Education Fund of the Board.
- (10) In case any claim is received from an unpaid investor after the refund process has been closed, the same may be made from the Investor Protection and Education Fund after necessary verification by the Administrator in consultation with the Recovery Officer:

Provided that the claim shall be made within a period of three years from the date of transfer of monies to the Investor Protection and Education Fund in terms of sub-regulation (9).

(11) The defaulter, and its officers who are in default as defined under section 2 of the Companies Act, 2013, as applicable, shall furnish an undertaking that they shall be liable for payment if any complaint is received in future by the Board from any investor.

Costs incurred in administration and repayment process

10.(1) The entire costs incurred in relation to the sale of properties, verification of investors' claims, remuneration of Administrator including the fees paid, if any, to the chartered accountant or valuer or such other person engaged by the Administrator and registrar and share transfer agent and all other expenses incurred in connection with the recovery and/or the repayment process shall be borne by the defaulter(s), failing which, the monies recovered by the Board shall be appropriated in priority to the other liabilities.

(2) The cost and expenses referred to in sub-regulation (1) shall be reasonable and directly related to and necessary for the act and purposes referred to in these regulations.

(3) Where the Administrator is appointed on the request of a person against whom an order for disgorgement or refund had been issued by the Board, the remuneration of the Administrator and the other costs incurred in respect of recovery and/or refund to the investors shall be borne by such person.

Priority in distribution of sale proceeds

11. The proceeds from the sale of properties of the defaulter shall be distributed in the following order of priority, namely, -

- i. the costs of administration incurred by the Board, if any, and the fees and charges payable to the Administrator and other persons appointed by the administrator in performing its functions under these regulations;
- ii. disgorgement and/or monies payable to investors:
Provided the Board may direct the Administrator to initiate the process of refund to the investors with the monies realized at the relevant time. For this purpose, the Administrator may call for claims in tranches
- iii. any other penalty or fees due from the defaulter to the Board under the provisions of the Act, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 or the Depositories Act, 1996.

Return of monies exceeding the liability.

12. In case the proceeds realised by way of sale of properties of the defaulter is in excess of the monies due from him under the certificate and the applicable interest and other charges, the excess money shall be paid to the defaulter after completion of three years from the date of completion of the refund process.

Filing of the repayment report.

13. Upon completion of the repayments to all investors or recovery of the disgorgement amount from the defaulter, the Administrator shall file a detailed repayment/recovery report to the Recovery Officer or Board, as the case may be, within the period as may be specified.

Part V – Disgorgement of amounts

14. The provisions of these regulations in relation to recovery of disgorgement amount ordered by the Board shall be applied in so far as it is applicable and the disgorgement amount so recovered shall be credited to the Investor Protection and Education Fund of the Board :

Provided the disgorgement amount shall be paid to investors only in cases where the eligible investors are identified in the order passed by the Board and the remaining amount, if any, after such payment, shall be credited to the account of Investor Protection and Education Fund of the Board.

Part VI - General obligations and responsibilities

Obligations and Responsibilities

15. An Administrator -

- a) shall maintain high standards of integrity, promptitude and fairness in the conduct of all his business.
- b) shall act with due skill, care and diligence in the conduct of all his business.

- c) shall not misrepresent any facts or situations and shall refrain from being involved in any action that would bring disrepute to the profession.
- d) shall act with objectivity during the course of his professional dealings by ensuring that all decisions are made without any bias, conflict of interest, coercion, or undue influence of any party, whether directly or indirectly connected to sale of properties, verification of claims and refund of monies.
- e) shall not acquire, directly or indirectly, any of the assets of the defaulter.
- f) shall maintain complete independence in all professional relationships and conduct the verification and refund process, as the case may be, independent of external influences.
- g) shall not conceal any material information or knowingly make a misleading statement to the Recovery Officer or the Board.
- h) shall not act with *mala fide* or be negligent while performing the functions and duties under the regulations.
- i) shall provide all information and records as may be required by the Recovery Officer within the time specified by him.
- j) shall ensure that confidentiality of the information relating to the sale of properties, verification and refund process, is maintained at all times:
Provided that the Administrator may disclose any information after obtaining written authorization of the Recovery Officer or the Board.
- k) shall disclose all costs towards the verification and refund process and endeavour to ensure that such costs are not unreasonable.
- l) shall comply with the terms and conditions of its appointment.

CHAPTER III

Action in case of default

By an Administrator

16. (1) The Recovery Officer may, for reasons to be recorded in writing, recommend for replacement of the Administrator, in case the Administrator has -

- a) failed to comply with the terms and conditions of appointment;
- b) engaged valuers or chartered accountants or such other persons who are ineligible to act so;
- c) failed to comply with any of the obligations and responsibilities specified under these regulations;
- d) acted against the instructions of the Recovery Officer or the Board; or
- e) acted in such manner that is prejudicial to the interest of the investors.

(2) Without prejudice to the action under sub-regulation (1), the Recovery Officer may recommend for initiation of appropriate action under the Act.

(3) On receipt of such recommendation or suo moto, the Board may take appropriate action against the Administrator or such intermediary or such other person engaged by the Administrator, under the Act including the following:

- (a) remove such Administrator from the Panel;
- (b) forward the matter to the Insolvency and Bankruptcy Board of India for appropriate action against the Administrator who is an Insolvency Resolution Professional; and
- (c) issue suitable directions restraining such person from engaging in activities in the securities market in his professional capacity.

(4) The Board shall replace an Administrator in the event his registration with the Insolvency and Bankruptcy Board of India is cancelled or suspended.

CHAPTER IV

Miscellaneous

Power of the Board to issue clarifications

17. In order to remove any difficulties in the application or interpretation of these regulations, the Board may issue clarifications and guidelines, as deemed necessary.

Forms

18. The Board or the Recovery Officer may specify the forms in respect of an order, notice, warrant, or certificate to be issued under these regulations.

AJAY TYAGI, Chairman
[ADVT-III/4/Exty./245/18]